SHRI K. R. GANESH: I introduce† the Bill.

I beg to move:†

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Pondicherry for the services of a part of the financial year 1974-75, be taken into consideration".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Pondicherry for the services of a part of the financial year 1974-75, be taken into consideration.".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up the clauses.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are two amendments to clause 3, but the hon. Member Shri Sezhiyan is not here to move them.

SHRI S. M. BANERJEE: He has moved out of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, I shall put the rest of the clauses together.

The question is:

"That Clauses 3 and 4, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 3 and 4, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. R. GANESH: I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

15.55 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—1974-75—*Contd.*

MINISTRY OF STEEL AND MINES—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up further consideration of the Demands for Grants under the control of the Ministry of Steel and Mines together with the cut motion moved thereon. Six hours were allotted of which 50 minutes were taken; the balance of time is 5 hours 10 minutes.

Shri G. P. Yadav to continue his speech.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have a submission to make. I am very happy Shri K. D. Malaviya is here. Since the Demands for Grants of this particular Ministry are being discussed, I want to make this request to him. He is aware that in a very big concern, the Hindustan Aluminium Corporation, known as HINDALCO, in Mirzapur, there is a lock-out and 7,000 workers have been rendered idle. I would request that this concern should either be taken over by the Centre or the hon. Minister should make a statement. The Chief Minister of UP has already intervened in the matter. I would request Shri Malaviya to say something on this.

श्री जागेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार) उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे कन्स्ट्रक्शन इन्जीनियर्स ऐसोसिएशन जब अपनी मांगों की

---

†Introduced/Moved with the recommendation of the President.

ले कर प्रबन्ध निदेशक के पास गये तो उन के ऊपर लाठियां चलाई गईं और उन को पुलिस यान में धनबाद ले जाया गया। वहां के प्रबन्ध निदेशक श्री खन्ना ने इन इन्जीनियर्स की मांगों को न मानकर उन के साथ ऐसा व्यवहार किया।

15.57 hrs.

[DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बोकारो के मैनेजिंग डायरैक्टर के इन किया-कलापों का क्या बोकारो स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा? इतना ही नहीं, उन का मकसद कुछ और है वे समझते हैं कि वहां कंस्ट्रक्शन के काम में बिहार इन्जीनियर्स ज्यादा हैं, इस लिये वे उन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं बिहार गवर्नमेंट के साथ एक करार हुआ था जिस मे यह तय हुआ था कि वहां के चीफ परसोनल मैनेजर के पद पर बिहार के आई० ए० एस० अफिसर को रखा जायेगा, लेकिन इस बारे मे ... ... नीति बदल गई। वह चाहते हैं कि ... ... चाहे ... मैनेजर ... ... बैठा कर काम करते रहें। इस कारण वहां ... कर्मचारियों मे भारी असन्तोष उत्पन्न हो गया है।

इतना ही नहीं,—वहां पर जो फाइनेन्स आफिसर श्री वर्मा थे उन के काम को भी उन्होने अपने हाथ में ले लिया। बोकारो स्टील प्लांट के कन्स्ट्रक्शन के जो जैनरल मैनेजर थे, उन के अधिकारों को भी वे अपने हाथ में ले रहे हैं। सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं —इस प्रकार से सारे अधिकारों का जो कन्सेन्ट्रेशन उन के हाथ मे हो रहा है बिहार पर इस का क्या असर होगा? क्या बिहार वासी जो बोकारो स्टील प्लांट मे अपनी योग्यता के आधार पर सेवा पर रहे थे, क्या इस तरह से उन के उपर कुठाराघात होने नहीं जा रहा है? क्या इस के कारण स्टील के उत्पादन में बड़ी कमी होने की आशंका नहीं है।

दूसरी बात— केवल यही एक घटना नहीं है, उन के उपर एक गम्भीर आरोप भी है, जिस के उपर सी०बी०आई० द्वारा इन्क्वायरी चल रही है। उन के उपर आयरन-पिग्ज की 47 वैगन्स के गोलमाल का आरोप है। जो आयरन-पिग्ज रशिया को एक्सपोर्ट होता था उस के बाद जो बच जाता था उस को छोटे छोटे मिनि प्लान्टस को दिया जाता था? उस आयरन-पिग्ज की 47 वैगनो को इन्होंने अन-आथराइज्ड ढंग से अनआथराइज्ड पार्टियों को बेचा और इस से करोडो रुपये की राशि कमाई है। इतना बड़ा स्कैण्डल श्री खन्ना के कारण हुआ है। इन स्कैण्डलों के कारण ही हमारा स्टील प्लांट घाटे में चलता है। इसी प्रकार का स्कैंडल भिलाई मे भी हुए हैं। स्क्रैप गुड्स के नाम पर वहां से अच्छे किस्म के लोहे को निकाला गया। और वहां पर करोड़ों का घोटाला हुआ जिसमें वहां के प्रबन्ध निदेशक तथा अखबारों मे यहां तक आ गई थी कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं। इन सब बातों की ओर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो स्टील प्लान्ट की उत्पादन का ह्रास होगा और फिर आप को भारी घाटा उठाना पड़ेगा।

16.00 hrs.

इस सिलसिले मे इंडियन एक्सप्रेस के 14 जनवरी, 1974 के अंक में लिखा गया है :

"The situation in the steel industry would appear to be extremely grave. This is underlined by the proposal of the Steel Authority of India Limited (SAIL) to make a sizeable cut in the target of steel production next year (1974-75). The target produced by SAIL is lower than of the previous two years. It hopes to be able to achieve production of only 6.7 million tonnes of ingot steel and 4.45 million tonnes of saleable steel. The

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

poor performance of the steel industry and under-utilisation of its capacity thus will not only continue but get worse.

This means that the gap between supply and demand of steel will grow wider and will add to the strains in the economy. It may be difficult to fill the gap by imports on any adequate scale because of the growing stringency of foreign exchange resources."

इतना ही नही, मेरा आपसे एक बात का और आग्रह है। जहा स्टील प्लान्ट की उत्पादन क्षमता का ह्रास हो रहा है और हमारा इस्पात उद्योग घाटे में चल रहा है, साथ ही साथ जो कुछ भी आप उत्पादन करते है उसकी वितरण प्रणाली भी ठीक नही है।

इसलिए वितरण प्रणाली में जब तक आप सुधार नही करते हैं तब तक आपका जो उत्पादन होता है उसके वितरण में गड़बड़ी रहती हैं तो उसकी जवाबदेही आप पर होगी।

इस सम्बन्ध में "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 20 जनवरी, 1974 में कहा गया है :

"Mr. Hiten Bhaye, Chairman of the Hindustan Steel, Limited, today urged the need for a rational and result-oriented distribution policy for steel, coupled with an all-out effort to step up production. Mr. Bhaya was speaking at a symposium on marketing of iron and steel products here. Mr. Bhaya said that in the present context it would be necessary to decentralise the distribution system, which would also mean that *ad hoc* arrangements and steps would be avoided."

इतना ही नही, आपकी डिस्ट्रिब्यूशन प्रणाली इतनी गड़बड़ है कि "हिन्दुस्तान टाइम्स", दिनांक 23 फरवरी, 1974 में यह बात कही गई है—स्टील मिसयूज्ड बाई बोगस फर्म्स। इस प्रकार की चर्चा महाराष्ट्र की विधान परिषद् में इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने की थी :

"Steel misused by bogus firms. 3,000 tonnes of steel were found misused from August, 1972 to March, 1973 by units registered as small scale industries, Mr. Kalyan Rao Patil, Minister of State of Industries. said today. He told the Legislative Council during question hour that these units, 251 out of 345, were found by Inspection Cell of the Industries Department existing on paper only. He said Central Directorate of Iron and Steel was considering appropriate action against these units."

आजतक इस प्रकार के जो घोटाले हो रहे हैं डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में उनके लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं ?

साथ ही साथ मेरा आपसे आग्रह होगा कि गांवों में रहने वाले ऐसे जो लोहार हैं जोकि हजारों की तादाद मे हैं, उनके हाथों जो रोजगार था जिसको अंग्रेजों ने छीना है, ब्रिटिश दासता के काल में उनके हाथ मेन थ से ला० का सारा का सारा उद्योग छीन लिया गया और आज लोहे के उद्योग में लगने वाले मे लोहार बेकार हैं, गांवों में तथा छोटे-छोटे कस्बों और शहरों में भी बेकार हैं, क्या उन के हाथ में काम देने की कोई योजना स्वीकार करने जा रहे हैं। इसके वास्ते मेरा आपसे आग्रह है कि डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के द्वारा ऐसे जो छोटे छोटे औजार हैं, ऐसे जो और कुछ इन्स मेटस हैं उको बनाने का काम उन के हाथों में दें ताकि उनको काम करने में सहुलियत हो सके।

इस्पात उद्योग की मांग पर चर्चा करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खनिज उद्योग का, उसके उत्पादन का एक बहुत बड़ा असर इस्पात उद्योग पर भी पड़ता है।

खनिज उत्पादन वास्तव में इस्पात एवं अन्य उद्योग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ अगर खनिज उत्पादन की हमारी क्षमता बढ़ती है तो खनिज सम्पदा को विदेशों में निर्यात करके हम फारेन एक्सचेंज भी पाते हैं। इस सिलसिले मे अगर हम देखते हैं तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे 436 करोड़ रुपया इस मद मे खर्च किया गया और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1140.02 करोड़ रुपए का हमने अपना लक्ष्य रखा। इस सम्बन्ध में अगर हम देखें तो पता चलेगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खनिज के उत्पादन के ऊपर क्या असर पड़ा। ज्यादा नहीं, केवल एक मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं। कोयले का उत्पादन 1970 में 73.70 मिलियन टन, 1971 में 71.82 मिलियन टन, 1972 में 74.77 मिलियन टन और 1973 में 77.20 मिलियन टन हुआ। जहां तक स्वर्ण उत्पादन का सम्बन्ध है, 1970 में 3241 किलो 1971 में 3656 किलो, 1972 में 3290 किलो और 1973 में 3257 किलो उत्पादन हुआ। इसके बाद लौह अयस्क में 1970 मे 31.37 मिलियन टन, 1971 में 34.26 मिलियन टन, 1972 मे 35.19 मिलियन टन और 1973 में 35.03 मिलियन टन उत्पादन हुआ। चूना पत्थर में 1970 में 23.84 मिलियन टन, 1971 में 25.07 मिलियन टन, 1972 में 25.68 मिलियन टन और 1973 में 23.34 मिलियन टन उत्पादन हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, उसके अंतिम वर्षों में जो उत्पादन के परिणाम आये हैं उसमें केवल कोयले में वृद्धि दिखाई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारत कोकिंग कोल ने जो उत्पादन बताया है और आपने जो दिखाया है कि बढ़ोत्तरी हुई है उसमें हमको आशंका है। मंत्री कोल माइन्स अथॉरिटी, एन०सी०डी०सी० और भारत कोकिंग कोल के जो बड़े बड़े पदं पर रहने वाले आफिसर्स हैं उन्होंने आंकड़ों के शब्दजाल में उत्पादन में बढ़ोत्तरी दिखाई है लेकिन ला आफ एकोनामिक्स के आधार पर यदि कोयले का उत्पादन बढ़ा है तो फिर मूल्य में कमी आनी चाहिए लेकिन वैसा हुआ नहीं है। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्य मे अंधाधुंध बढ़ोत्तरी हुई है। पहले हमको गांवों में चाहे कोयले को जलाने के काम मे हो या ईंट उद्योग के लिए या शहरों मे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के काम के लिए बिहार में 1 रुपया या सवा रु या मन कोयला मिलता था लेकिन नेशनलाईजेशन के बाद कोयले की कीमत 8 रुपए मन हो गई है। यदि आप कहते हैं कि अंतिम चरण में लास्ट ईयर हमारे नैर कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ा है तो हमको उसमें आशंका है। अगर उत्पादन बढ़ा है तो फिर गड़बड़ी क्यों हुई, कीमत क्यों बढ़ी। ला आफ एकोनामिक्स के आधार पर तो यदि उत्पादन ज्यादा होता है तो कीमत गिरनी चाहिए लेकिन वैसा नहीं हुआ।

कोयले की जहां तक ढुलाई का प्रश्न है, आप कहते है उसके कारण गड़बड़ी होती है और उसके लिए आपने एक कमेटी बनाई है। उसके डिस्ट्रिब्यूशन, उसकी लोडिंग कराने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए आपके अपने विभाग के डिप्टी मिनिस्टर हैं वह उसके चेयरमैन है कोल माइन्स एथारिटी के। अब एन०सी०डी०सी० के स्पेशल अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड ने भी कंट्रोल रूम बनाना, लेकिन उस का परिणाम क्या हुआ? दो दो बार बैठकें हुई उन की सिफारिशें भी आपको आयी लेकिन रेल मंत्रालय के कान पर जूं नहीं रेंगती **और इसलिये आपको रेल वैगन मिलने में असुविधा होती है रैकमेंडेशन के बाद भी।

SHRI M. C. DAGA (Pali): He has made certain allegations against a Minister. He has not given them in writing. This should be expunged.

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : सभापति महोदय,** पहले जिस अनुपात मे कोयले के लिये वैगन उपलब्ध होते थे, आज नही हो रहे हैं। क्या वजह है कि अब कोयले के वितरण और ढुलाई मे कोई भी अन्तर नही आया ?

MR CHAIRMAN Besides the hon Minister is not present in the House

AN HON MEMBER You should withdraw it

SHRI G P YADAV No question of withdrawing I am drawing the attention of the hon Minister of Steel and Mines so that he may take immediate action to see that coal is supplied in adequate quantities

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सभापति जी, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं माननीय सदस्य से कहू कि वह मेरा ध्यान तो दिला सकते है ऐसे प्रश्नो की ओर जो उन्हे इस समय परेशान करते है। लेकिन हमारे किसी सहयोगी के बारे मे कुछ ऐसे कहना जो बिल्कुल निराधार है और जिस का सम्बन्ध बहस से न हो मैं समझता हू बहुत ही अनुचित बात है और मैं उन से प्रार्थना करूगा कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान न दिया करे। अगर वह उन शब्दो को वापस ले ले तो बहस मे ज्यादा अच्छी तरह मे हम एक दूसरे की बात बात को समझ सकते हैं।

डा० कनाम (बम्बई दक्षिण) राजनीतिक दृष्टिकोण मे किसी बात को कह देना यह ठीक नही । इसलिए वह उन शब्दो को वापस ले ले ।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : सभापति महोदय, वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है, उन के खिलाफ हम ने प्रधान मंत्री को और राष्ट्रपति को मेमोरेन्डम दिया है। अगर उन के भ्रष्ट तरीके और भ्रष्ट आचरण के विषय मे मैं कुछ बोलता हू तो वापस लेने का कोई प्रश्न नही है। यह मेरा मौलिक अधिकार है। जिस चीज़ को मैं जानता हूं उस को कहने का हमे अधिकार है । इसलिये मैं ने कोई बात एसी नही कही है जिसे वापस लू ।

MR CHAIRMAN Several Members have pointed out that you have taken a different line of an otherwise useful role of bringing certain matters to the notice of the Minister concerned But you have brought in other persons, particularly, a Minister of the Government First he is not present here Secondly, the manner in which you are making these allegations is not also quite in tune with the high standard which we follow in this House So I would appeal to you not to make such remarks You might have submitted a memorandum Those things are not relevant to the discussion now going on I would appeal to you not to make such remarks and I would also appeal to you to take the guidance given by the hon Minister, Shri Malaviya That would be in conformity with the standards that we expect in a debate like this So, you withdraw the allegations There are other ways open to you He has to respect his colleagues He has I suppose withdrawn it

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव ठीक है साहब ।

चौथी योजना के अन्त मे कोयले का जो उत्पादन था उस मे बढ़ा कर साढे 13 करोड टन करने की योजना सरकार की पाचवी पचवर्षीय योजना मे है और उस पर लगभग 850 करो० मंत्रालय का खर्च होगा और उस धनराशि का प्राविधान पांचवी योजना मे है । मेरा कहना है कि केवल आकडो से काम नही चलेगा, बल्कि मैं चाहता हू कि कोयले का उत्पादन वास्तविकता मे

**Expunged as ordered by the Chair

देश में बड़े कोयले के उत्पादन से ही हमारी सारी की सारी इंडस्ट्रीज, चाहे बिजली की हो, कल कारखाने हों, चाहे रेलें हों चलती हैं अतः उसे और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उस मशीनरी को जिस में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो शब्द जाल के आंकड़ों में आप को डालते है, उन के ऊपर भी पैनी निगाह रखी जाये ताकि पांचवी योजना के लक्ष्य पूरे हो सकें।

सभापति जी, राष्ट्रीयकरण के बाद, कोकिंग कोल के राष्ट्रीयकरण के बाद उत्पादन में ह्रास हुआ और कोकिंग कोल के राष्ट्रीयकरण के बाद वितरण प्रणाली इतनी भ्रष्ट हो गई है कि समूचा हमारा आर्थिक औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा है। क्या उस सम्बन्ध मे हमारे मंत्री महोदय पुनर्विचार करने के लिये तैयार हैं? नीतियां देश के लिये, जनता के लिये बननी है। अगर उस नीति के कारण हम को कठिनाई हो, देशवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पडता हो तो क्या उस नीति मे परिवर्तन करने की आवश्यकता नही है? इस के लिये मैं चाहूंगा मंत्री जी इस के ऊपर पुर्नविचार करें।

कुछ ही दिन पहले माननीय खान मंत्री ने लखनऊ मे कहा, और किसी ने शायद उन से पूछा कि क्या आप नेशनेलाइजेशन से पीछे हट रहे हैं, जैसे व्हीट टेक ओवर में पीछे हटे? तो मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी लाश पर ही पीछे हटेंगे। मेरा उन से निवेदन है कि केवल भावना के साथ नेशनेलाइजेशन को नहीं जोडना चाहिये। वितरण मे जो खामियां आई उस के कारण लोगों का जो दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया, सारे उद्योग धंधे ठप्प हो गये, बिजली के उत्पादन मे कमी आयी, उस को भावना से नहीं जोड़ना चाहिए। नीतियां जनहित के लिये होती है और इस में परिवर्तन की गुंजायश रहती है। अगर आप इस प्रकार का उद्घोष भ्रष्टाचार मिटाने के लिये, बेरोजगारी मिटाने के लिये, चीन के द्वारा ली गई 14 हजार वर्ग मील भूमि को निकालने के लिये करते तो मेरी समझ में यह बात आती। लेकिन भावना के साथ इस प्रश्न को न जोड़ा जाये। आज देश में एक साधारण रसोई बनाने वाले के लिये या जो कारखाने वाले लोग हैं, बिजली के कारखानो में कोयले की कमी के कारण जो संकट आया है, वितरण प्रणाली में जो दोष आया हैं इस के कारण हमारा अर्थ-व्यवस्था, औद्योगिक ढांचा और आम लोगों का दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस विषय पर सोचते हुए पुर्नविचार करें ताकि देश की बिगड़ती हुई स्थिति को बचाया जा सके।

अन्त में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। सरकार ने कोयले का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन मजदूरों को क्या मिला? जब सरकार राष्ट्रीयकरण करने के बाद उस के डिस्ट्रिब्यूशन में सुधार नही कर सकती और उत्पादन-क्षमता को नही बढ़ा सकी, तो फिर उस को इस बारे में पुर्नविचार करना चाहिए। साथ ही मैं चाहूंगा कि कोयला-उत्पादन और अन्य उद्योग-धंधों मे जो मजदूर काम करते हैं, उन को उन उद्योगो में साझीदार बनाया जाये। अगर मजदूर उन उद्योगों में साझीदार बनता है, पार्टनर बनता है, उन मे मालिकाना हक प्राप्त करता है, तो उस की उत्पादन-क्षमता बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि इस्पात उद्योग और कोयला खदानो में काम करने वाले मजदूरों को उन उद्योगों में भागीदार बनाया जाये, ताकि वे समझ सकें कि ये हमारे उद्योग हैं। आज स्थिति यह है कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में लेती जा रही है, वह स्वयं उन उद्योगों को चला नहीं सकती है और मजदूरों को सहयोग देने और उत्पादन बढ़ाने का आह्वान करती है।

सरकार इन उद्योगों में पूंजी लगाये और मजदूर अपना श्रम लगायें। उन उद्योगों

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने के लिए और उन में जो त्रुटियां आ गई हैं, उन को दूर करने के लिए मजदूरों को भागीदार बनाया जाये, उन का सहयोग और योगदान लिया जाये। ऐसा करने से हमारे इन उद्योगों की उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि होगी।

सरकार ने वैगनों की सप्लाई के लिए जो कमेटी बनाई है, उस की सिफ़ारिशों को कौन देखेगा? आज स्थिति यह है कि वैगन नही मिल रहे हैं। समस्तीपुर डिविजन मे, जो एन० ई० रेलवे का सदर-मुकाम है, सत्तर, अस्सी गाड़ियां बन्द हो गई है। जब स्वयं रेलवे की यह स्थिति है, तो फिर वह दूसरे उद्योगों के लिए क्या करेगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में पुर्नविचार करें, ताकि लोगों को आसानी से और समय पर कोयला मिल सके।

MR CHAIRMAN: Mr. Yadav, for the purpose of our records, to make your statement of withdrawal of allegations clearer, I am taking it as withdrawn.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं ने आप के सामने सारी बातें रखी है। मैं समझता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नही कही है, जिस को वापिस लेने का प्रश्न उठता है।

MR. CHAIRMAN: Let us be clear. The hon. Members have objected to your statement making allegations. You have been good enough to withdraw it. I wanted to make it clearer for the purpose of our records.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : मैं विदड्रा करने के पक्ष में नही हूं।

MR. CHAIRMAN: Then, you are going back.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : सभापति महोदय, आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बैठे हुए है। मैंने कहा है कि हम उन के भ्रष्ट आचरण के खिलाफ़ राष्ट्रपति से मिले हैं—और 51 एम० एन० एज० और 11 एम० पीज० के हस्ताक्षर के साथ मिले हैं। उन का इतिहास रंगा हुआ है। मैं नही समझता हूं कि मैंने उन के सम्बन्ध में आज कोई विशेष बात कही है।

MR CHAIRMAN: I wanted you to understand the strong feelings expressed by several Members of this House to the categorical allegations you have made against a colleague of yours. The hon. Minister, Mr. Malaviya, also pointed out that during this debate. of course, you could make criticisms against the Ministry but to drag in the name of another person, another Minister, is not in tune with the practice here. So, I made an appeal to you and you said, *theek hai.* I just wanted to make it clear for the purpose of our records.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : मैं श्री मालवीय की भावना से सहमत हूं।

MR CHAIRMAN: So, the record will be that you have withdrawn it.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव नही, मैंने वापस नहीं लिया है। वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। रात-दिन हाउस मे** चर्चा होती है। रेलवे मंत्रालय मे पहले बड़े बड़े अफ़सर घूस लेते थे। अब तो और जुल्म होने लगा है। यह चर्चा तो रात-दिन होती है। मैंने क्या कहा है, जो मैं विदड्रा करूं।

MR. CHAIRMAN: In this case, let us be fair, you have made very specific allegations against the Minister.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : कमेटी की सिफ़ारिशों के बावजूद रेल की ढुलाई में कोई तरक्की नहीं हुई है और रेलवे वैगनों

**Expunged as ordered by the Chair.

की सफाई में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है ।

MR. CHAIRMAN: That is a different matter; that is not at all the issue here.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I appeal to him, Sir, to withdraw those things; otherwise, you have the powers to expunge.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : सभापति महोदय, जिन बातों की चर्चा सारे देश भर में है, यदि उन का उल्लेख किया गया है, तो उस में कौन सी बुरी बात है ? जो आलोचनायें की गई हैं, वे रिकार्ड पर रहनी चाहिए । उन को रिकार्ड से नहीं निकालना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Kachwai was not present here at that time. Several hon. members have raised objections to this statement. This has to be decided because I took it that he had withdrawn those allegations.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव: मंत्री महोदय की भावना से मैं सहमत हूं ।

MR. CHAIRMAN: I would like to be fair to hon. members. And I expect some response from Mr. Yadav also. In the interest of high level of discussion, I am appealing to him.

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह कोयला खदानों में होने वाले काम या कोयले के वितरण की टीका-टिप्पणी करें । अगर वह उसमें भ्रष्टाचार देखते हैं, तो वह उसके बारे में भी टीका-टिप्पणी कर सकते हैं । उनको इस का पूरा अधिकार है । मैंने यह कभी नहीं कहा है कि वह ऐसा न करें । मुझे जो सफाई देनी होगी, वह मैं अपने भाषण में दे दूंगा । मैं बता दूंगा कि वह गलत आधार पर ऐसा कह रहे हैं । लेकिन अगर वह एक माननीय सदस्य, और खास तौर से मेरे कुलीग, के बारे में कोई ऐसी बात कहते हैं, जो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, जिसका मैं सही नहीं समझता हूं, और उनके बारे में वह वैयक्तिक रूप से कोई आक्रमण करते हैं, तो मुझे यह कहने का पूरा अधिकार है कि वह उसको वापस ले लें और सभापति महोदय, आप उनका वापिस लेने के लिए कहें, और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको रिकार्ड से निकाल दें ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Yadav, you come forward now. You know the principles on which one should base allegations.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय खान और इस्पात मंत्री की भावना से मैं सहमत हूं । मैंने कोई वैयक्तिक बात नहीं कही है । मैंने रेलवे मंत्रालय की चर्चा की है कि वह भ्रष्टाचार का अड्डा है ।

SHRI K. D. MALAVIYA: That is all right. Those portions regarding specific allegations against any member which were not justified should be taken out.

MR. CHAIRMAN: If I remember aright, and it will be verified from the records, Mr. Yadav made certain specific allegation personally against Mr. So-and-so. That is a very serious allegation and I cannot allow that kind of allegation. I appeal to the good sense of the hon. Member. But if you say it was done as a sort of a general statement, it does not tally with your earlier statement. If you

[Mr. Chairman]

just say, 'I did not mean like that, I was only making a general statement', that is all right. But if you pin-point a person and say like that, then it becomes a very serious personal allegation, and it does not befit a Member of Parliament. I will appeal to your good sense to withdraw it.

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : सभापति महोदय, यह मैं तीसरी बार कहता हूं कि इस्पात और खान मंत्रालय के मंत्री महोदय की भावना से मैं सहमत हूं। मैंने व्यक्तिगत बात नही कही। रेलवे मंत्रालय की बात कही और वहां इस तरह की बातें होती हैं। उसके खिलाफ हम लोग राज यहां सदन मे कहते हैं।

MR. CHAIRMAN: Then if he had made any personal allegation against any specific person, it will be expunged.

SHRI DARBARA SINGH (Hoshiarpur): It should be expunged

श्री हुकम चन्द कछवाय नही, सभापति महोदय, आप क्या चाहते हैं कि हम उनकी तारीफ करें ? वह गलत काम करें और हम उनकी तारीफ करें ? तारीफ करने के लिए तो उधर के सारे लोग बैठे हुए हैं... (व्यवधान) ....हम उसके लिए नही आए हैं। अच्छा काम अगर कोई मंत्री करेगा तो हम निश्चित उसकी तारीफ करेंगे लेकिन जो व्यक्ति भ्रष्ट होगा उसकी तारीफ हम नही कर सकते उसकी हम निन्दा करेंगे। ...(व्यवधान) ...उसको रेकार्ड पर रहना चाहिए (अगर आरोप जो लगाए है वह सब गलत हैं तो जिन मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए हैं वह मंत्री आकर सफाई दे सकते हैं। लेकिन रेकार्ड पर रहना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: I cannot allow it.

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): Mr. Yadav appreciated the view-point placed by the hon. Minister. I think it should be closed there and the Chair should not be asked to expunge anything because at no stage he has withdrawn. I think the matter should be closed there and the House should proceed further.

MR. CHAIRMAN: You understand the background. He has already made a specific allegation against a specific Minister. Later on, he says, 'I only made a general statement.' Then how does it tally? In order that we accept his later statement that he was only making a general statement, we accept his later statement and the earlier one stands removed so that it may be in tune with his later one clarifying the earlier statement.

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : सभापति महोदय मैं इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। जो मांगे मंत्री महोदय ने रखी है और अगली पंचवर्षीय योजना मे उन्होंने जो प्रावधान रखे हैं वह ऐसे हैं कि जिनसे जो इनका मकसद है वह शायद पूरा नही होगा। जितनी मांगे उन्होंने रखी हैं वह कम करके रखी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनमे बढोत्तरी की जाये। अभी हमारे पूर्व वक्ता महानुभाव ने और बातो को कहते हुए यह बात भी कही कि और कुछ हुआ या नही हुआ लेकिन कोयले का उत्पादन बढा है। सब से अहम बात यह है कि कोयले का उत्पादन क्यों बढा? मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह तभी सम्भव हुआ कि जब कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर कोयले का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो

यह संभव नहीं होता कि कोयले का उत्पादन बढ़ता। ऐसे लोग जो राष्ट्रीयकरण के विरोध में हैं, राष्ट्रीयकरण की बात जिनको समझ में नहीं आती उनके मुंह से भी अगर यह बात सुनने को मिलती है कि कोयले का उत्पादन बढ़ा है तो मुझे सतोष होता है, हालांकि पूरे देश में एक भ्रम को फैलाने की चेष्टा की जाती है, जब भी कहीं कोई सवाल होता है किसी भी कारणवश किसी उद्योगधन्धे में कोई कमी आती है तो कोयले का नाम लोग लेना शुरू कर देते हैं। पिछली बार जब रेलवे में आंशिक हड़तालें कहीं-कहीं हुईं या और भी बात हुई जिसके फलस्वरूप इस्पात उद्योग में कुछ काम घट गया तो वहां पर भी यही सवाल उठाया गया कि कोयला नहीं मिलता इसलिए स्टील प्लान्ट बन्द होने वाले हैं। बात दरअसल यह थी कि कोयले की कमी नही बल्कि ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से यह हुआ था। स्टील प्लांट में सिर्फ कोयला नही बल्कि और भी रा-मैटीरियल उपलब्ध नही हो रहा था लेकिन जब हाउस में सवाल उठाया गया तो सिर्फ कोयले का नाम लिया गया। तो एक भ्रम फैलाने की बात चल रही है कि राष्ट्रीयकरण की वजह से कोयले का उत्पप्दन नहीं हो रहा है जबकि दरअसल स्थिति यह है कि कोयले का उत्पादन बढ़ा है और अभी जो राष्ट्रीयकरण के सबसे बड़े विरोधी है उन्होंने भी इस बात को मंजूर किया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?

उत्पादन बढ़ा है यह बात सही है लेकिन देश में संकट अभी बढ़ा है कोयले का इसमें भी कोई दो मत नहीं हो सकते। कोयले का उत्पादन बढ़ा तो वह कोयला गया कहां, थोड़ी मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं। आपको पता है कि देश के पावर हाउससेज में कोयले का कजम्पशन बढ़ा है। देश के स्टील प्लान्ट्स में कोयले का कन्ज्यूमशन बढ़ा है। अकेले पावर हाउसेज को जहां 1971—72 में 15 मिलियन टन कोयला देते थे आज उनको 21 मिलियन टन कोयला देना पड़ा है। स्टील प्लान्ट्स में जहां 13 मिलियन या करीब सवा तेरह मिलियन टन देना पडता था वहां आज साढ़े तेरह मिलियन टन देना पड़ा है। अगली पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है कि अकेले स्टील प्लान्ट्स की खपत 34 मिलियन टन हो जायगी और पावर हाउसेज की 43 मिलियन टन हो जायेगी। केवल इन दो विभागों में करीब 73 मिलियन टन कोयला खप जायेगा और रेलवे तथा देश के और भी छोटे छोटे उद्योग धंधे जो हैं, स्माल कन्ज्यूमर्स हैं, जो ब्रिक बर्निंग के लिए कोयला चाहते हैं या घरों में जलाने के लिए जो कोयला लेना चाहते हैं उनकी मांगों की हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे जो क्षमता हमने इस समय रखी है उसके मुताबिक 135 मिलियन टन का जो प्रावधान रखा है अगली पंचवर्षीय योजना में अगर उस पर आप स्टिक करना चाहते हैं तो देश को जो जरूरत है उसके मुताबिक कोयला हम नही दे सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगली पंचवर्षीय योजना में कोयले के संबंध में पुनर्विचार होना चाहिए और इसका जो उत्पादन लक्ष्य हमने रखा है, जो क्षमता रखी है उसे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

आज कितनी दर्दनाक हालत है उसका सिर्फ एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूं। हालांकि कोयले का उत्पादन बढ़ा है लेकिन

[श्री दामोदर पाण्डेय]

अकेले ब्रिक बर्निंग में कितना लास लोगों को हो रहा है इसका आप अनुमान इससे लगाये, 1969—70 में प्रति दिन कम से कम 550 वैगन उनको देते थे, 70—71 में 345 कर दिया था, 72—73 मे 386 कर दिया था और आज प्रति दिन हम कुल मिलाकर सिर्फ 70 वैगन उनको देते हैं। तो बात सही है लोगों को कोयले की कमी होगी। देश मे कोयला कितना भी बढ़े लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग-धंधे चलाने वाले लोग हैं या जो ब्रिक बर्निंग के लिए कोयला चाहते है अथवा घरों मे जलाने के लिए जिनको कोयला चाहिए उनको अगर पर्याप्त मात्रा मे कोयला नही मिलेगा तो यह बात कहने के लिए हम कह सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट कम है, उनको कम परसेंटेज मे कोयला चाहिए, लेकिन उनके सामने कठिनाई रहेगी। मेरे ख्याल में इस तरह से देश में कोयले का संकट न हो, स्माल कन्ज्यूमर्स को कोयला मिल सके इसके लिए कोयले के उत्पादन लक्ष्य में बढोत्तरी होनी चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए।

सभापति जी, जो नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद इसको सम्भालने की जिम्मेदारी मंत्री महोदय की थी। मंत्री महोदय ने उस जिम्मेदारी को सम्भालने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत सा काम बाकी है, जो अभी भी उनको करना है। आज राष्ट्रीकरण के बाद यह कहने मे तकलीफ होती है कि बहुत से कोयला खदानो मे काम करने वाले मजदूरों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। है। बहुत के कोयला खदानों में मजदूर आज भी उन्हीं झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनमें पहले रहते थे, उनके रहने के लिये मकान नही है। बहुत सी कोलियरीज मे दवा-दारू की व्यवस्था नही है। इन कामों मे तो तनिक भी विलम्ब नही होना चाहिए था, लेकिन दो साल के बाद भी यह व्यवस्था न हो पायी। मैं मंत्री महोदय से उम्मीद करता हूं कि वे इस काम को जल्द से जल्द अपने हाथ में लेंगे और पूरा जल्दी कराने की व्यवस्था करेंगे।

आज यह एक सब से बड़ी भयावह बात हो गई है कि एक तरफ तो पीने का पानी नही है, दवादारू की व्यवस्था नही है, रहने के लिए घर नहीं है, दूसरी तरफ उनको खाने के लिये अनाज भी नही मिलता है। कोयला खदानो मे काम करने वाले मजदूरो के लिये राशन की व्यवस्था भी नही है। राशन की जो भी व्यवस्था है, वह उनको पहुच नही पाती है। क्या यह आप की जिम्मेदारी नही है कि उन के खाने के लिये अनाज दें? इस के पहले जब देश मे अन्न संकट हुआ, कोयला खदान मे काम करने वाले मजदूरो के लिए अलग से व्यवस्था की गयी थी, लेकिन आज यह पहला मौका है जब कोयला खदान के मजदूरो को खाना नहीं मिलता है, उन को अनाज नही मिल पाता है, पैसा देने पर भी नही मिल पाता है—यह गम्भीर समस्या है।

मंत्री महोदय को जानकारी होगी—नेशनलाइजेशन एक्ट मे इन्होने कम्पेन्सेशन के लिये. प्रोवीजन रखा था, करीब 30 करोड रुपया रखा था। मैं बहुत सी आइटम्ज को छोड़ देता हू, केवल दो आइटम्ज के बारे में बतलाना चाहता हूं—पुराने मालिकों के पास मजदूरों का जो बकाया पैसा है, मुझे

पता नहीं वह आप कहां से पूरा करेंगे। मैं सिर्फ गोरखपुरी प्रथा का उल्लेख करना चाहता हूं जो वहां पर पहले चलती थी। इसके अन्तर्गत मजदूर 11 महीने से एग्रीमेंट पर काम करने के लिये आते थे और वे मिल-मालिक उन से 11 महीने तक काम करा कर उनको पैसा नहीं देते थे, बड़ी बेरहमी के साथ उन से काम लिया जाता था, इस तरह का 26 करोड़ रुपया बकाया है .....

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे (गोरखपुर): अब 28 करोड़ रुपया है।

श्री दामोदर पाण्डे: इसी तरह से प्राविडेंट फण्ड में 11 करोड़ रुपया बाकी है। कम्पेन्सेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। इस तरह से मजदूरों की साल-साल भर की कमाई उन को नहीं मिल पाई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं—मजदूरों के लिए आपने कानून में जो व्यवस्था कर दी है, उतनी ही काफी नही है, बल्कि उन को यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन मजदूरों का जो भी पैसा होगा वह आप किसी भी तरह से उन को देने की व्यवस्था करें, इस के सम्बन्ध में आप को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इण्डिया फायर ब्रिक्स का एक कारखाना मेरे क्षेत्र में है और उस के ही बगल में आसाम सिलनाइट का कारखाना है। जिस तरह से इस कारखाने के मालिकों ने बदअमनी कर के उस कारखाने को बन्द कर दिया था, उसी तरह की हालत आज इण्डिया फायर ब्रिक्स के कारखाने में हो रही है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आसाम सिलनाइट का कारखाना सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इण्डिया फायर ब्रिक्स का कारखाना भी तीन महीनों से बन्द पड़ा है, वहां के मजदूर दर-दर के भिखारी बन रहे हैं, उनको रोजी नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूं कि इस्पात मंत्रालय इस पर गम्भीरता से विचार करे और उस कारखाने को अपने हाथ में ले ले जिससे वहां काम करने वाले 1200 मजदूरों की रोजी-रोटी की सुरक्षा हो सके।

आज कोयला खदानों की जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में केवल एक-दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां एक तरफ हमारे मजदूरों ने संगठित हो कर सरकार का साथ दिया, वहां के अधिकारियों के साथ सहयोग दिया, लेकिन आज वहां काम करने वाले अफसर उनको परेशान कर रहे हैं। परेशान ही नही कर रहे हैं बल्कि मेरा तो कहना यह है कि वे काम में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं। अभी तक मजदूरों की हड़ताल की बात सुनने में आती थी, अफसरों की हड़ताल नही होती थी, लेकिन अब वहां अफसरों की हड़ताल होती है। वे पुराने लोग जो पहले मालिकों की तरफ से शोषण करते थे, जब यह महसूस करने लगे कि उनके शोषण का रास्ता बन्द हो गया है, तो वे नई शोषण प्रणाली से नये ढग से अपना राज्य कायम करना चाहते हैं—मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें।

खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिये जो व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह नहीं हो रही है। राष्ट्रीयकरण के बाद हमारे मजदूर सरकार से यह अपेक्षा रखते थे कि उनकी सुरक्षा के लिये और अधिक व्यवस्था की जायेगी,

[श्र द न दर पण्डे]

लेकिन बदकिस्मती से आज यह कहना पडता है कि मजदूरो के लिये यह एक सपना-सा बन कर रह गया है । आज खदानो मे एक्सीडेन्ट का रेट बढ गया है । इस काम के लिये जो सुपरविजन होना चाहिये था, जो व्यवस्था होनी चाहिये थी जिस कारगर ढग से व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह सुपरविजन नही हो रहा है । मैं चाहता हू कि इस पर मंत्री महोदय ध्यान दे और व्यवस्था को मजबूत बनावें । आज वहा के अफसरान दफ्तरो मे बैठ कर ताश खेलते है अपनी यूनियन की बाते करते है, जो जिम्मेदारी उनको सौपी गई है उस जिम्मेदारी की बाते नहं करते है ऐसे अफसरों की निगरानी की जानी चाहिये और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये ।

इन शब्दो के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हू ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर): सभापति जी, यह मत्रालय हमारे देश के विकास के लिये मूलभूत आधार इस्पात और कोयला पैदा करने वाला है और इस मायने मे स्वभावत बहुत महत्वपूर्ण है । आज के जमाने मे न सिर्फ उद्योग बल्कि खेती का विकास भी इस्पात और कोयले के विकास के बिना सम्भव नही है और इसी पृष्ठभूमि मे जब कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो देश के जन-जीवन ने उस का स्वागत किया था । मगर, सभापति जी, इस राष्ट्रीयकरण के साथ ही, इस टेक-ओवर के साथ ही सरकार ने बडी कोशिश की कि उसे किसी तरह से नाकाम बनाया जाये और इसी लिये राष्ट्रीयकरण होते ही पुराने कोयला खदान के मालिकों को उन्ही कोयला खदानों को बरबाद करने का पूरा अवसर दिया गया, उन के बहकावे पर उन के लठैतो को कारखाने मे भरती किया गया और इस तरह से करोड़ो रुपया उन्हे नाजायज तौर पर दिया गया.

श्री एम० एस० संजीवी राव (निजामाबाद) · सही बात नही है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मै निराधार बात नही कहता हूं । कुछ लाल-बुझक्कड उधर बैठे हुए है जो कभी कभी बूझ जाते है ।

सभापति जी, एक काल-एटेन्शन मैंने इसी सदन मे घोरी खदान मे जो गोली काण्ड हुआ था, 6–3–1973 को, उस के बारे मे दिया था, उस समय मुझे उस का जवाब नही दिया गया था और कहा गया था कि आगे जवाब आयेगा, उस के बाद वह मत्री जी ही चले गये । लेकिन अब पिछले महीने मेरे पास जवाब आया है जिस मे कबूल किया गया है कि जबूर कर के, लठैतो के नाम पर घेरा डाल कर पुराने मिल मालिको ने 76 हजार रुपया रुकवा दिया । उस ऐशारेंस के फुलफिलमेन्ट के रूप मै मुझे 15 फरवरी, 1974 को जवाब मिला है जिस मे कहा गया है—

"A decision was accordingly taken at 10-30 PM by Deputy Custodian General to pay at a flat rate of Rs 4 per head per day on the basis of the attendance as per wage bills submitted to Coal Mines Authority In respect of Quarry No 2, it was decided that the workers would be paid at the rate of Rs 2 per head per day only and the balance paid on scrutiny, because it was learnt that the number of inductees there was very large"

यह तो उस समय की बात है । बाद मे यह साबित हो गया कि यह सब जाल था । इसके लिए अब क्या हुआ है ?

यह भी कि :

"Subsequent assessment shows that out of an advance payment of Rs. 76,000, an amount of Rs. 51,000 has already been adjusted against the work done through the same contractors as verified by the same authority. An amount of Rs. 7000 has been paid back by the contractors."

76 हजार रुपए में यह कहते हैं उन्हीं को फिर काम का ठेका देकर उनके उस एमाउन्ट को एडजस्ट करा लिया गया है । बाकी उन्होंने अपने घर से पैसा नहीं दिया है जिन्होंने घेर कर गोली चलवाई थी ।

यह भी दिया है :

"It is unfortunate that more or less as a result of this pressure the Custodian-General died of a heart attack."

He succumbed to it and he died.

जिससे इनके अफसर की भी मृत्यु हो गई गोली चली, बहुत से लोग मारे गए और उस कन्ट्रैक्टर को, एक्स ओनर को इनाम में फिर कंट्रैक्ट दिया गया । तो जो 76 हजार रुपया उस ने जबरन नाजायज़ तौर पर ले लिया था अपने लठैतियों के लिए वह रुपया उससे वापिस लिया जाये । मैं जानना चाहता हूं अभी भी उन व्यक्तियों को जेल में रखने के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं ? अगर अभी भी उनको काम दिया जा रहा है तो फिर कोयले के उत्पादन में सैबोटेज होगा या नहीं कोयले के उत्पादन और वितरण में जो अव्यवस्था फैल रही है वह होगी या नहीं ? तो यह उनके रिकार्ड की बात है जिसका मैं ने हवाला दे दिया है और इसको देखकर आप समुचित कार्यवाही करें ।

इसी तरह का एक हवाला मैं और देना चाहता हूं । जिस समय इस्को का उत्पादन बहुत नीचे चला गया था तो देश हित को ध्यान में रखकर सरकार ने उसको अपने प्रबन्ध में लिया था । लेने के बाद पुराने सभी प्रबन्धक कायम रह गए । उसमें ऐसे लोग रह गए जिनकी जालसाजी पकड़ी गई । जिन्होंने अपनी कार्यवधि पूरी हो जाने के बाद जाल किया । जाली टेलेक्स मेसेज भेजा । उस मेसेज को मैं आपके जरिए मन्त्री महोदय को सुना रहा हूं । इसको वे सुनें । यह 6—3—72 का है जिस मेसेज में उन एन० आर० दत्त, जिनको कस्टोडियन जनरल बनाया है इन्होने बर्नपुर का, उन्होंने कलकत्ता इस्को के पास भेजा :

"Reference 5726 CB of 6-9-72; the actual date of birth is 3-1-13 though it is recorded as 3-6-1912."

1912 के बदले में 1913 मेरे जन्मवर्ष को कर दिया जाये । यह उन्होंने तब दिया है जब यह जाल मालूम हुआ है । तो ऐसा जो जालसाज है उस के पास इस्को का प्रबन्ध आज भी पड़ा हुआ है । (व्यवधान) तो इस तरह के लोगों को रखा गया । अभी भी प्रबन्धकों का वह पूरा काफिला वहां मौजूद है । ऐसी स्थिति में हम आशा नहीं करते कि ऐसे लोग उत्पादन बढ़ाने में हमारे मददगार होंगे । तो इस तरह की हालत है । यह सरकार एक तरफ देश हित को ध्यान में रखकर या जनता की मनोभावना को खयाल में रखकर या शायद वोट लेने के लिए एक अच्छा कदम उठाती है तो उसके साथ चार बुरे कदमों को इस तरह जोड़ देती है कि लोगों के सामने निकम्मी नजर आ जाये । इसी का नतीजा यह है कि बहुत दिनों के बाद जो आशा लोगों को बंधी थी कि कोयले और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होगी उसमें आज फिर हर जगह

[श्री भोगेन्द्र झा]

संकट नजर आ रहा है। अभी हाल मे बोकारो के 1500 कन्स्ट्रक्शन इंजीनियर हड़ताल पर है। वे अपनी माग लेकर गए थे अभी 27–3–74 को मैनेजिग डायरेक्टर के पास मिलने के लिए। मिलने के लिए उन्हे समय दिया गया था पहले से। उसके मुताबिक वे गए जब गये तो पुलिस बुलवाई गई लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारिया हुई और गिरफ्तार करके बहुत जेल भेजे गए और बहुत घायल किये गए। यह मैं इजीनियरो की बात कह रहा हू, मजदूरो की बात नही है जिन पर सरकार को लाठी चलाने की आदत हो गई है और उनपर लाठी चलाने की बात को भारी बात के रूप मे गिना भी नही जाता है। यह बोकारो मे अभी हुआ है और बोकारो के निर्माण कार्य मे भारी नुकसान पड रहा है। 15 सौ इजीनियर्स का अभी भी बड़ा आन्दोलन है। अगर माननीय मन्त्री जी ऐसे मसलो पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान नही देंगे तो जो उन्होने अभी पिछले दिनो एलान किया था कि वे इस्पात के मामले मे विभिन्न कारखानो को एक तरह से विकेन्द्रित करके कुछ ज्यादा अधिकार देने जा रहे उसमे ऐसी परिस्थिति मे बहुत बडा घाटा हो जायेगा। जो व्यक्तिगत पूजीपति हैं वे अपने मुनाफे की फिक्र मे भी रहते हैं। हमारे प्रबन्धक जिनको सामूहिक सम्पत्ति मे विश्वास नही है, जिनको पब्लिक सेक्टर के अस्तित्व मे ही विश्वास नही है, जो जायज या नाजायज पैरवी या डिग्री के आधार पर नौकरी मे आते हैं उनमे विश्वास नही है कि सार्वजनिक क्षेत्र से रहे। कुछ टाटा के चुनकर इस्पात के मालिक बना दिए जाते हैं जिसका नतीजा बड़ा भंयकर होता है। अभी बोकारो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं खन्ना साह उनके बारे में खबर है—कहां तक सही है? मत्री जी खण्डन कर दें तो मुझे खुशी होगी—कि 47 वैगन लोहा ब्लैक के रुप मे उन्होंने टाटा को भेजा है। मैं चाहूंगा मंत्री जी खण्डन करे। मेरे पास सबूत है, मैं फिर सदन मे लाना चाहूंगा उन्होंने 47 वैगन लोहा ब्लैक के रूप में टाटा के पास अन-अथराइज्ड रूप मे भेजा है। मैं चाहूंगा सी० बी० आई० से इसकी जाच करवाई जावे। मुझे यकीन है जबतक जमशेदपुर का कारखाना टाटा के हाथ मे रहेगा तबतक रूरकेला या दुर्गापुर या बोकारो का कारखाना कभी भी मुनाफा नही कर सकेगा क्योंकि टाटा के आदमी दुर्गापुर मे घुसाये गए हैं, बोकारो मे घुसाये गए हैं और रूरकेला मे घुसाये गए हैं। वहां से वे सस्ते मे कच्चा माल या तैयार माल भेजते हैं। दो चार लाख लेकर 25 लाख का माल भेजते हैं। इसलिए उनके रहते वहा कुछ होने नही जा रहा है। आपको बहुत प्रेम है टाटा से—अब तो वे एयरमार्शल हो गए हैं—तो उनको आप कोल माइन्स एथारिटी का चेयरमैन बना दीजिए जैसे एयर इडिया का बना दिया है लेकिन बीच मे टाटा को रखकर बगल मे आपके पब्लिक सेक्टर के कारखाने कभी भी क्षमता पर काम नही कर पायेंगे, कभी भी मुनाफे पर नही चल पायेंगे जबकि उन्हीं के आदमी नीचे से ऊपर तक उनमें भरे हुए हैं। उनको एक मुशाहर तो आप सरकार की ओर से देते हैं लेकिन उससे कई गुना मुशाहर उनको टाटा की ओर से मिलती रही है। टाटा लगातार बोकारो के निर्माण के खिलाफ थे, रूरकेला के खिलाफ थे, खुलेआम उसके खिलाफ थे कि इस्पात कारखाने नही बनने चाहिए।

ऐसी स्थिति में जो संकट पैदा हो रहा है हमारे उत्पादन के क्षेत्र में अगर सरकार उन बातों पर ध्यान नहीं देगी तो हमारे उत्पादन पर यह संकट गहरा होता चला जायेगा। हिंडालको एक ऐसा कारखाना है जहां पर सरकार की ओर से सारी सहूलियतें दी गई है। कारखाने के लिए कुछ सहूलियतें दी जायें इसमें दो रायें नहीं हैं क्योंकि देश के औद्योगिकरण के लिए वह आवश्यक हो सकता है लेकिन सारी सरकारी सहायता आम जनता के बल पर दिए जाने के बाद आज बिड़ला जी के कारखाने का नतीजा क्या है? मेरे पास कई तार आ गए हैं, आपकी इजाजत से में चाहूंगा वह तार सदन की टेबिल पर रख* दूं और बोकारो के इंजीनियर जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके फोटो भी सदन की टेबिल पर रख दूं। मंत्री जी देखें किस तरह का सुलूक उनके साथ किया गया है। उस तार के मुताबिक हिंडालको के प्रबन्धकों ने कारखाना बन्द कर दिया है 12 तारीख से। स्टाफ के लोगों पर भीतर जाने की रोक लगा दी गई है। मैंने मन्त्री जी से बात की थी। मुझे पता चला है, मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि इनको धोखा दिया गया, बिड़ला जी की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिजली देना बन्द कर दिया है इसलिए हम कारखाने में लाक-आउट करने जा रहे हैं लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इनके विभाग के ज्वाइन्ट सेक्रेटरी ने यू पी विद्युत बोर्ड के अधिकारियों से बातें की थीं और वह बातें गलत साबित हुई। तो गलत-बहाना करके भारत सरकार के मंत्रालय को धोखा दिया गया और 12 तारीख से कारखाने पर तालाबन्दी कर दी गई है। अब जो मजदूर हैं वे क्या करें? इसलिए वहां कभी भी अशांति का खतरा है। उत्तर प्रदेश की सरकार या पुलिस, खास करके मिर्जापुर के डी० एम०, एस० पी० कभी भी बिड़ला के खिलाफ जाने की हिम्मत रेंनहीं करते। मैं समझता हूं उनकी वफादारी बहुगुणा से ज्यादा घनश्याम दास बिड़ला के प्रति है क्योंकि वे बिड़ला का पैसा खाते हैं। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं रेणुकोट गया था, एक सभा थी, उसके लिए जब मैं अपने माइक के पास पहुंचा तो एक एस० डी० ओ० आये और कहा कि हम 144 लगा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया तो उन्होंने कहा अशांति हो जायेगी। मैंने कहा मेरे भाषण से अशांति क्यों हो जायेगी, उन्होंने कहा अशांति हो जायेगी। मैं ने कहा ठीक है, आपको अशांति का खतरा है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि शांति रहेगी। अगर मुझे गिरफ्तार कीजियेगा तो अशांति होगी, अगर मुझे रोकियेगा तो अशांति होगी। मैने उनकी अवज्ञा करके वहां भाषण दिया। बाद में वे आये गिरफ्तार करने। हम ने कहा कि नहीं अब मैं अगर गिरफ्तार हो जाऊंगा तो अशान्ति हो जायेगी, मैं भाषण दूंगा, मैंने भाषण दिया, शान्ति की अपील की मजदूरों में। बाद मे गिरफ्तार कर के मुझे ले जाने लगे तो लोगों ने घेर लिया। फिर उन्हों ने कहा कि लोगों को समझाइये मैं ने कहा कि अब तो मैं गिरफ्तार हूं, मैं कैसे भाषण दे सकता हूं, आप तो माइक छीन कर ले गये हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बोलिये शान्ति के लिये नहीं तो पचासों लोग घायल हो जायेंगे। फिर वही लोग लाउट स्पीकर ले आये, 144 को तुड़वाने के लिये मुझ से कहा। मैं ने अपील की और शान्ति हुई, और मुझे पकड़ कर मिर्जापुर जेल में ले गये। उत्तर प्रदेश की सरकार रेणुकूट में पंगु बनी हुई है। मुख्य मंत्री जी का खत

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper was not treated as laid on the Table.

[श्री भोगेन्द्र झा]

मेरे पास आया है लेकिन उन की बात नही चल रही है। केन्द्रीय सरकार धोखे मे रह रही है और वहा भी उत्पादन बन्द हो रहा है और कारखाने के मालिक इस तरह से जानबूझ कर मिले बन्द कर रहे है क्यो कि भारत के करोड़ पतियो की यह नीति हो गई है कि उत्पादन घटाओ मुनाफा बढाओ । कम पैदा कर के ज्यादा कीमत पर बेच कर के मनाफा कमाओ । अधिक पैदा करने से जो देश को फायदा होता है उस मे शायद ज्यादा मुनाफा न होने पाये। यह चीज हमारे कोयले के उत्पादन में बाधा ला रही है जिस के बनने वाले कोयला खदानो के मालिक उस के बारे मे मुझे खबर मिली है मैं आशा करता था कि हमारे मित्र माननीय पांडे जी का ज्यादा जानकारी होगी लेकिन मैं समझता हूं कि पुराने कोयला खानो के मालिक यह साजिश कर रहे है कि कोयला ... और जान ... खानो पर कोयला ... लगा हुआ है ... कोयला नहा जा रहा है रेल गाडिया बन्द है हमारे समस्तीपुर डिवीजन मे जहा 5 गाडिया चलती थी अब केवल एक चल रही है चार बन्द है । जो रेलगाड़िया कोयले की कमी के कारण बन्द है उन को कोयला नही मिल रहा है और मत्री जी कहेगे कि कोयले का ढेर पडा हुआ है पिट हैड पर क्योकि वैगन नही मिल रहे है। तो ... एक चक्रव्यूह मे फस गये है जिस के पीछे मालिको का हाथ है । पुराने मालिक वैगन के लिए रिश्वत देते थे अब कौन रिश्वत देगा । और दूसरी तरफ वही पुराने खानो के मालिक ठेकेदार और ... बन रहे है । और वह समझते है कि अगर एक टन ले जायगे दुगुनी कीमत पर बचेगे तो ज्यादा मनाफा होगा । अगर ज्यादा कोयला ... और हम मुनाफा हुआ तो हमारे मुनाफे मे बढती नही होगी । और मुझे शक है कि भारत सरकार के उच्चतर अधिकारियो मे से है और शायद प्रधान मत्री के मत्रिमडल से भी कुछ सदस्य उन को आश्वासन दिये हुए है कि अगर देश मे कोयले का सकट काफी हो जाय जिस से चूल्हा जलाने वाले और ईट बनाने वाले हगामा कर दे कि राष्ट्रीयकरण के चलते ऐसा हो गया है और फिर कुछ मित्र सदन मे है जो कहेगे कि राष्ट्रीयकरण के कारण ऐसा हुआ तो फिर पुराने मालिको को कोयला खाने लौटा दी जायेंगी, इसीलिए वे सकट पैदा करते। इसलिये यह एक साजिश है । जहा ... कोयले का भडार है उसी के ... मे ईंट नही पक सकती है चूल्हा नही जलता है कोयले की कमी के कारण कोयले की चोर बाजारी कर के लोग लूट रहे है और देश सकट मे पडा हुआ है । रेल गाडिया बन्द है । चाहे भी किसी मत्रालय का दोष हो नतीजा यह है कि देश सकट मे पडा हुआ है । ऐसी परिस्थिति मे जो ... और कोयले का मामला है उस मे विकेन्द्रीकरण करने के पहले मै चाहूगा इसी माग की स्वीकृति के साथ साथ मत्री जी सदन को यह आश्वासन दे कि यदि वह आटोनामी दने जा रहे है कारखानो को तो उस के साथ ही मजदूरो का प्रबन्ध मे हाथ होगा और इस के लिये कोई बहाना नही बनायेगे ।

17 hrs

अफसर लोग कहते है कि मजदूर यूनियनो मे एकता नही है । उस बात को छोडिये मजदूरो का गुप्त मतदान के आधार पर प्रतिनिधित्व लीजिये और प्रबन्ध समिति मे मजदूरो को लीजिये और उन पर भरोसा कीजिये और खुल कर के प्रबन्ध के कार्यों मे

उन को लगाइये । जिन अधिकारियों के बारे में भ्रष्टाचार साबित हो चुका है उन को निकालने की कोशिश कीजिये ।

टिसको को आप ने दो साल के लिये लिया था जो समय जुलाई में बीतने वाला है । ऐसा न हो कि जो उत्पादन मजदूरों ने बढ़ाया आप के टेक ओवर के बाद उस के बाद फिर आप उस कारखाने को पुराने मालिकों को लौटा दें । तो उस के राष्ट्रीयकरण का आप ऐलान करें ताकि फिर यह न हो कि पुराने मालिक को वापस करे। इसलिये मैं कहूंगा कि कोयला और इस्पात के बारे में जो नीति है वह कामयाब हो उस के मुताबिक संगठन के ढाचे में परिवर्तन कीजिये और मजदूरों का सक्रिय सहयोग लीजिये । पुराने जो मालिक है उन को इस से सदा दूर रखिये वरना वही मसल मछली की रखवाली बिल्ली के हाथ में, ऐसा न कीजिये क्यों कि वह कभी कामयाब नही हुई है । अगर आप मालिको पर बहुत खुश हैं तो उन को दूसरे विभाग में ले जाइये, कोयला विभाग में न रहने दीजिये ।

मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी इन बातो पर ध्यान देंगे, कही ऐसा न हो कि कल उनके हाथ में नाकामयाबी रह जाय और देश के भारी उद्योग के जो विरोधी हैं उन को कहने का हथकंडा मिल जाय, बहाना मिल जाय जो कहा करते थे कि इस्पात के कारखाने बेकार है, कोयले का राष्ट्रीयकरण बेकार है, जो भिलाई और बोकारो कारखाने के बनने के ह थे, न के हाथ मजबूत न हो जायें कि देश वगैर कारखाने के ही चले ।

अन्त में सभापति जी अगर आपकी आज्ञा हो तो यह कागज में टेबिल पर रखना*चाहता हूं ।

MR. CHAIRMAN: This will be examined.

SHRI CHAPLENDU BHATTACHARYYIA (Giridih): I have been really trying like a Gasandra during the last three years for captive thermal power plants. I made that point in my Budget speech on this ground in 1972 and made the point again on 2-8-72 and raised the issued in the Consultative Committee. On 15-3-73, I said that there were a large number of gassy mines in Raniganj coal fields particularly and to prevent disaster you must have not only Matheno meter, but automatic recorders and monitors for these gassy mines and if necessary it should be imported. Within four days the Jitpur disaster struck. The last three years have been locust years. Captive power plants did not come up. Automatic recorders, monitoring system and Mathenomotors had not come. Steel production has gone down by 1.45 lakh tonnes and it is worth about Rs 45 crores. Coal production could have been 2 to 3 million tonnes more. There would have been no Jitpur. I want to ask the Minister through you. Mr. Chairman: how many Jitpurs are necessary to move your Ministry to ensure safety of the workers and to have captive thermal power plants. When the DVC failed you, when the Ministry of irrigation and power failed you and when the State Electricity Boards have failed you, must you still be looking at the posterior of these departments? If there are more Jitput the morale of the workers would be shaken. I suggest that an emergency organisation for the mining sector be set up with readily available equipments such as conventional pumps. Switch Gears, Suspension and Mobile Winding gears to combat dangers of

*The Speaker *not* having subsequently accorded the necessary permission, the document was *not* treated as laid on the Table.

[Shri Chaplendu Bhattacharyyia]

subsidence, inundation, fire damp and stores and equipment made available within an hour or two through Charged off stores. There should immediately be evolved a scheme of Rationalisation of Stores. Procedure in the mines under C M.A., N.C.D.C. & B.C.C.L., Hindustan Zinc, Hindustan Copper, N.M.D.C. This includes charged off stores In view of heavy investment in public mining sectors, C.M.A., B.C.C.L, N.C.D.C., Hindustan Copper and Hindustan Zinc, NMDC we want Pilot Sectors or pilot mines to assess and evaluate the different types of mining machinery and have the basis of what is called value engineering.

There is no standard costing yet and crores of rupees have leaked out because we have no standard costing and we have no rational stores procedures. The leakages have to be stopped.

Preventive maintenance does not exist either in the coal mines or in the steel plants Printed check-list for preventive maintenance is a routine thing in the National Coal Board in England. They take air samples and dust samples all the time. They have a special maintenance-cum-safety cell attached to each mine This is because we are going in for a larger mechanisation programme, eruption of methane gas is bound to be larger and the hazards are going to increase So, unless we take remedial measures, we will be exposing the coal miners to increasing hazards.

You have framed Plans. Last May, 1973 when the energy crisis was round the corner, I wrote to the then Minister of Steel and Mines, Mr. Pai, suggesting that we should have a decade plan, not a five year plan but a decade plan, of 350 million tonnes for coal so that we can plan properly not only the coal production but more important than that, its movement and the logistics without which coal production cannot take off.

Now, you have the Annual Plan and you have done various exercises. But, have you projections of steel-coal ratio, KW of electricity-coal ratio, wagon ton miles-coal ratio as part of the plan for increased output of coal? What proposals you have to lower these ratios? Have you thought of alternatives to steel pipes so that we can reduce the consumption of steel, as they are doing in the US Bureau of Mines. Then, Sir, lead is a very vital factor because of the diesel and fuel crisis. I have suggested that we must open up more areas nearest to the consuming centres. One hundred million tonnes is the estimated consumption of the domestic sector and we are supplying only seven million tonnes. You can understand the discontent prevailing in the countryside. I have suggested the opening of Bali Hill Seam with 15 million tonnes at Giridih and 40m. tonnes at Hura basin of Rajmahal coal field should be immediately opened up and by strip mining we can immediately increase their output to 3 million tonnes They are probably, within 50 to 70 or 80 miles of the Ganges We can carry the coal upto Allahabad, if not upto Kanpur by barges.

While preparing the Plan, what do you propose to do about scarcity of timber, electric drills, cement and sand on a short term as well as on a long term range? Sir, there are large reserves of valuable metallurgical coal in stocks, barriers, ribs and shaft pillars in Jharia estimated at about 500 million tonnes and 8 8 million tonnes of the finest metallurgical coal in Giridih. Do you propose to write them off or try new mining techniques like Chess Board mining or any other technique available to extract as much of coal as possible Now, the price of coking coal is Rs 239 Even at Rs. 140 a tonne, if this is the cost of extraction, you shall have reached your break-even point and is worth while, as there is no greater compulsion on matters of reconsideration of policy as on the issue of coking coal. I suggest a coal consumers' Council to advice CMA, NCDC

and BCCL, as they have in Great Britain.

Then, Sir, I come to steel. We should rather expand the existing steel plants which will take only three years than going in for new plants. We should have smaller investments that way rather than going in for larger capital investments. This lather will involve a long gestation period of about seven to eight years. In the present situation of constraints on domestic resources and foreign exchange, we cannot afford not to expand the existing steel plants. I had suggested then and I again suggest now that we should have half a dozen captive thermal power plants. A few of them should be mobile thermal or power producing plants as they have now abroad so that we can stiffen supply during peak loads in those mines or steel plants where the requirement of power has suddenly shot up.

In the matter of the Ministry of Steel, there are administrative anomalies. The Chairman of SAIL happens to be the Secretary of the Ministry of Steel. That is an anomally which must be rectified. The Technical Director of SAIL is also Chairman of Mecon Ltd. In such interlocking arrangements, administrative and techcal problems will not come to the surface and Parliament will be denied the full picture.

We supported the induction of SAIL with great expectations. But what has been their performance? Everybody hoped for 90 per cent utilisation of capacity. It is hardly 60 per cent. now. We have to import Rs. 200 crores worth of steel. We gave them fullest authority and autonomy. We made really little Czars of public sector Directors and Chairmen. If there have failed to deliver the goods, they must go. "Hire and fire"—this is the others of American industrialism. We cannot have it half-way. If they have failed to deliver the goods, let them go. We do not want to interfere in their day-to-day work. On a close scrutiny of working of the stock yards on of the sale of scrap, it was found that in one day Indian and Iron Steel Co. lost Rs. 12 crores because when the auction was on and the bid had gone up to Rs. 19 crores, after Rs. 5 or 7 crores, they withdrew some items from the auction bid. What happened in IISCO is happening in Durgapur and has happened in Bhilai. You have what is called misroll. Variation of plus or minus 4 per cent is allowed under ISI. There is deliberate misrolling. You increase it by 4.5 per cent and it goes as misroll at half the price! If this extent of corruption is there can you ever make the steel plants efficient and paying? They are charging at Rs. 1800 per tonne and the black market rate is Rs. 2800. For material, for hurrican lanterns, in 1965 the price was Rs. 500 per tonne. Now it is selling at Rs. 3800. I do not know whose brain wave is this dual pricing policy. It is a dangerous brain wave and it has created black market. Those who purchase it in large lots and those officers who sell it to them are all very happy because the margin is Rs. 1000 a tonne. I suggest that members of the Consultative Committee in that region should was associated with a probe plant by plant. Things have gone too far and unless we are able to stop these leakages, we will not be able to fight inflation and roll back the prices and the capital investment cost will go on soaring.

I have suggested that if steps are taken, 3 per cent increase in fuel efficiency can be very easily achieved. That will save us crores of rupees in the coming years in our fuel bill.

Then, I have suggested a performance-cum-efficiency bonus not only to workmen but also to officers in steel and coal. We have to get the best out of them. We have to get a sense of participation. We have to regard the honest officers and pick up the smart ones. The tricky ones, the go-getter ones should be identified and thrown out of the organisation. Unless we can do this, we can never make the grade. Now, that performance-cum-efficiency bonus could start, say, at

[Shri Chaplendu Bhattacharyyia]

60 per cent, the present average efficiency of steel mines and that rate should increase with increased utilisation factor at a slab rate. That can be worked out There are 1-2 types of efficiency bonuses worked out by industrial engineers in advanced countries. We can have an efficiency bonus tailored to every industrial unit in the steel or mines sector.

They always say that labour is inefficient I would like to read out Mr Wilkinson, a top-notch engineer of America has to say about it in his book·

> "Labour is as efficient as management plans it to be Planning for efficient labour is the responsibility of the management A worker will not plan his own efficiency while a foreman may do some planning They are primarily doers, not planners."

So, you have to separate the function of planning from production

We have had many alibies in the past, the shortage of power, labour indiscipline, etc In some cases, I labour indiscipline in some steel plants labour indiscipline in some steel plants for reasons best known to them What my hon friend, Bhogendra Jha, said happened in a steel plant also

Now, the materials management, the data processing, the preventive maintenance, the details of lubrication, all these things, are important items in steel plants Our steel plants have already aged due to bad maintenance Such an old steel plant as that of the Tatas can do 65 per cent while our new steel plants, our coke oven batteries are falling apart The Giridih coke oven is running after 45 years But the new coke oven batteries in steel plants are already old in course of 5—10 years

We have had always alibies, always something wrong or other, the power shortage, the labour indiscipline and all that Now, we have another alibi of allotment of wagons. So, we must separate the cause from the excuse, the chaff from the grain. A way must be found so that we come to know from our pragmatic approach the way to expand production. It is not that difficult as is being made out We can bring down the price of steel by expanding production.

श्री धनशाह प्रधान (शहडोल) मै इस्पात और खान मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हू और मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू कि खान मे काम करने वाले मजदूरो की जीवन रक्षा के बारे मे और जहा वे काम करते है, जहा से कोयला निकालते है, हा उन की सुरक्षा के बारे मे, जो मशीन व इस्तेल करते है माउस के बारे मे तथा जो वहा गैस और खराब हवा बनती है उस से जो उन के ऊपर असर पडता है उन बातो के ऊपर वह ध्यान दे । यह तमाम कठिनाइया उस के रास्ने मे होने के कारण कोयले के उत्पादन मे कमी आती है और इस प्रकार की व्यवस्था सारे देश की कोलियरीज मे चल रही है । सरकार ने इस के लिए जो धनराशि निर्धारित की है 1974–75 के लिए वह धनराशि कम है, उस धनराशि को और अधिक बढाया जाए ।

मै यह भी निवेदन करूगा कि खदान मे दैवी दुर्घटनाए जो होती है शासन उन दुर्घटनाओ को रोक सकता है । जैसे पिछले मार्च मे मध्य प्रदेश के शहडाल जिले की भनपुरी कोलियरी मे छत गिरने से 7 व्यक्तियो की मृत्यु हो गई । मैं जानना चाहूगा आप ने उस के बारे मे कौन सी कार्यवाही की, कौन सी जाच की जब कि 7 लोगो की मृत्यु हो गई । धनबाद के इसपेक्टर ने उस के चार हिस्से किए थे और उसमे से एक पिलर काट लेने का आदेश दिया था लेकिन वहा के मैनेजर ने चारो हिस्से काट लिए जिस मे छत बैठ गई और 7 आदमी उसमे मर गए । तो एक और जहा हमे उत्पादन

बढ़ाने की ओर ध्यान देना है वहां साथ ही साथ मजदूरों के जीवन की सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। कोयला खानों में ऐसी व्यवस्था की कमी है और वहां जीवन सुरक्षा की व्यवस्था करने में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। उस के ऊपर भी आप ध्यान दें अन्यथा उत्पादन में कमी और मजदूरों में असंतोष बढ़ेगा और अफसरों के भ्रष्टाचार की वजह से भी आप का यह काम ठीक तरह से नहीं चल सकेगा।

मैं यह सुझाव देता हूं कि कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन बीमा करना आवश्यक है। मेरी बातों का उत्तर देते समय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन बीमा किया जायगा। साथ ही जो हमारे आज के वैज्ञानिक और दूसरे इस विषय के जानकार लोग हैं उन का सहयोग इस कार्य में लिया जाना चाहिए कि किस तरीके से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर के कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और इस रिसर्च के लिए सरकार ने जो रकम रखी है उसे बढ़ाया जाय ताकि वैज्ञानिक लोग इस में अधिक रूचि लें और नये नये तरीके इस के लिए निकालें जिस से खदानों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

दूसरी बात-खदानों में उत्पादन क्यों कम हुआ ? क्यों कि वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। पिछले दिनों गाड़ी लादने का जो रेट उन्हें मिलता था वह 3 रुपये 80 पैसे था। यह रेट बहुत कम था। इसको न बढ़ाने की वजह से बीरसिंह पुर कोलियरी के मजदूर सीधे हड़ताल पर चले गए जब कि कंसिलिएशन का फैसला था कि अमुक तारीख तक यह कर देना चाहिए। लेकिन वह नहीं किया और इस बात को ले कर मजदूर हड़ताल पर चले गए। कौन जवाबदार है ? वे किसी भी मांग को लेकर हड़ताल कर देते हैं। इस लिये कोयला खदान में काम करनेवाले मजदूरों की सुविधाओं, दवा, पानी, तथा अन्न आदि की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, इस के लिये जो प्रावीजन आप ने किया है, यह बहुत कम है। इस के लिये और अधिक रकम मंजूर की जाए।

अपने देश के वैज्ञानिकों की कमेटी बनायें जो अपने देश में यह पता लगायें कि कोयले की और खदानें कहां पर हैं, इस काम के लिये और अधिक धन खर्च करें जिस से देश में कोयले का उत्पादन बढ़ सके।

कोयला खदानों में उत्पादन के संबंध में जो बाधायें आती हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। हमारे अधिकारियों का व्यवहार मजदूरों के साथ ठीक होना चाहिये, मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है, वह ठीक से मिले। आज मजदूरों में काफी असंतोष है, अधिकारी उन के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं—हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिस से उन के दिल से भय दूर हो सके और वे लगन से अपना काम करें।

हमारे जो मजदूर और कारीगर अच्छा काम करते है उन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये—जैसे भिलाई इस्पात कारखाने में जो धमन-भट्टी थी. उसका ढक्कन रबर का था जो हर समय गल जाया करता था-उस पर लाखों रुपया खर्च होता था। हमारे एक मामूली टैक्निशियन ने लोहे का ढक्कन बनाया जिस से वह काम ठीक हो गया और समस्या हमेशा के लिए सुलझ गई। लाखों रुपये की बचत हुई। इस के लिये उस व्यक्ति को 50 रुपये की तरक्की दी गई। इसी तरह से जो इन्जीनियर्स है, फिटर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं उन को प्रोत्साहित करने के लिये उन को काम दिये जाय, तरक्की दी जाय अग्रिम प्रशिक्षण दिया जाय और इस के लिये आप इस बजट में अधिक रुपये की व्यवस्था करें।

[श्री धनशाह् प्रधान]

खदानो मे सफाई तथा सुरक्षा के कामो पर विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है। मजदूर जब खदानो के अन्दर काम करते हैं तो उन की सुविधाओ तथा सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि मजदूर खुश होगे तो उत्साह से काम करेगे तो इस से हमारा उत्पादन बढेगा, देश मे कोयले की कमी दूर होगी और इस तरह से वे राष्ट्र के सकट मे हाथ बटा सकेगे।

सिंगरोली खदान मे अभी भी जितना कोयला है, मैं समझता हू कि उस से दस गुना अधिक है, मैं जानना चाहता हू कि उस के दोहन के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है। इस दोहन प्रक्रिया मे मशीनो को क्यो प्राथमिकता दी जा रही है, जब कि उस क्षेत्र मे इतनी बडी बेरोजगारी फैली हुई है। ऐसा महसूस होता होता है कि हमारे रोजगार मत्रालय और खान तथा इस्पात मत्रालय मे काई तालमेल नही है। मैं चाहता हू कि आप इस ओर विशेष ध्यान दे, मशीनो की अपेक्षा मजदूरो को प्राथमिकता दी जाय। इस काम के लिये आप जो धनराशि मन्जूर करने जा रहे है, वह बहुत कम है, इस के लिये और अधिक धन की व्यवस्था की जाय।

अन्त मे, मैं पुन कुछ बातो को दोहराना चाहता हू-कोयला खदानो मे काम करने वाले मजदूरो का लाइफ इशोरेस करे, उन के काम की सुविधाओ पर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि ये उत्साह से काम करे और देश का उत्पादन बढायें। इन शब्दो के साथ मैं इन मागो का समर्थन करता हू।

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore) Mr. Chairman, Sir, the Steel Ministry, after Mr. Malaviya took over, has brought enthusiasm in the workers because they feel that here is a Minister who can deliver the goods after Mr. Mohan Kumaramangalam. The steel prices have increased. Our steel production in 1970-71 was 46,27,400 M T In 1971-72 it was 478,300 M T In 1972-73 it was 54,08,600 M T In 1973-74 it was 345,000 M. T In six months of 1973 ending in November 1973 steel production declined by 100,500 M T of ingot and 262,200 M T of saleable steel as compared to the same period in 1972 The shortage for 1973-74 was about 851,600 M T of ingot steel and 742,500 M T of saleable steel Even the state of affairs of pig iron was never good

What was the world production in 1973 and may we compare ourselves with the world production? In USA it was 136 5 M T In USSR it was 131 M T In Japan it was 119 3 M T In Germany it was 49 5 M T In India, what is the position? The production is only 5 million tonnes This is the state of affairs

The Steel Authority of India suggested a target of 6 37 M T of ingot steel and 4 45 M T of saleable steel in the annual plan for 1974-75 which was below the production target of 7 098 M T of ingot steel and 5 441 MT of saleable steel to be produced during 1973-74

According to the draft Fifth Plan our domestic demand for finished mild steel was about 10 M T by 1978-79 But the target is too unrealistic in the face of non-availability of 50 per cent of basic requirements as well as the production level of 5 per cent It was estimated that all steel plants would produce jointly 8 8 M T in 1978-79 But what is the position today? I want to bring to the notice of the hon Minister that he should kindly note that our progress as far as the steel production is concerned is not good

I will now devote a little towards the administrative set up in the steel

plants. Mr. Malaviya will agree that workers demand justice from the administrators. The worker, if he has to get justice has to go from court to court. I know about Rourkela Steel Plant being a trade union worker there. Their cases are pending in the Supreme Court. Do you agree that a worker whose minimum wage is Rs. 240 can afford to go to the Supreme Court? Can he get legal aid at all? So, Mr. Malaviya should kindly see that there should be a point where it should stop and the worker should get justice. He may make arbitration compulsory also. I know that trade union workers have been sent out from service in Rourkela; two trade union leaders wanted jobs; their cases went up to the Prime Minister of the country. The General Manager assured saying, if you submit your regrets, I will re-employ, either in Rourkela or in Bokaro. They submitted their regrets. For the last many years they are roaming about without having any justice, without having any employment. Where stands the guarantee of somebody's word? Being the General Manager, he must stick to his word. 800 workers who were the security guards in Rourkela Steel plants were retrenched because under the CISF rules they were asked for the option, saying, either you opt for the CISF or you go. They said, we are old workers, we will remain as security guards, we will not opt. So, they were retrenched. Then there was pressure from the Government of Orissa. There was pressure from the trade union. 200 were taken. Then again there was pressure from the Chief Minister. 400 were taken. Like that for two years, without any justice, without any system, without any process, the workers were in distress and now there remain 42 security guards. The hon. Minister may kindly note that 42 security guards are going from door to door with begging bowl to maintain their livelihood in Rourkela. And what is their future?

The Department now says that 'from your conduct, we now find that you are not good security guards. 'Well, Sir, if they would have opted for the Central Security Force, they would have got the job. But, since they did not opt for it, you are now going back to the records of ten or twelve years before to find out what they did. And, the C.C.R. means the impression of the head of the department.

I want to raise another point. The Steel Ministry once decided that the deputationists from the State Government—I mean the deputationists who are working in the Steel Plants—have to opt either to remain with the company or they will revert back to the parent organisation. What has happened to that? There is a local demand that the deputationists from the Government of Orissa are stopped in the Rourkela Steel Plant; now, the hammer came in either to opt for the steel plant or to revert back to Government of Orissa. So, the Deputy General Manager who was shunted back from Government of Orissa was working in the Steel Plant. He worked there for six months. There was a tussle between the Deputy General Manager and the General Manager and so he had to come back to Orissa Government. Such is the regional trouble in Rourkela; such is the atmosphere and it is difficult to bring regional harmony in Rourkela. Government of India is probably aware of it. Why is it that there is some defect in the personnel relations between the officers and the workers? There is some defect in the management of the personnel department; there is some defect in the attitude of the administrators towards the workers. There is no regional trouble as such. The trouble emanates between the relationship of the management and the workers. It is that which vitiates that atmosphere. That is why I suggest to the hon. Minister that they should exactly find out why the workers were put under M.I.S.A. and why they were detained under D.I.R. And why one of the officers who was

[Shri Shyam Sunder Mohapatra]

put under M.I.S.A. has got promotion? Where exactly lies the trouble? Where exactly there is a feeling between Oriyas and Bangalis, Bengalis and South Indians? Who were responsible for this? I say it is the policy of the management which is responsib'e for this.

Then, Sir, corruption is let large in many steel plants. It is difficult for the hon. Minister to know where the corruption is—whether it is in the auction of this scrap or in the distribution of steel. It is a very difficult process; it is so intricate that the Minister cannot understand it unless he goes deep into it

We have now got many officers from the Tata's—from the private sectors—into our Ministry. They are competent people. Why are they not able to stop it? Have they relations with the private sector? Have the officers who have been brought from the private sector to man our ministry any acquaintance in the trading circle? How is it happening? You can get any amount of steel in the market. In the name of scraps, good steel is going out. It is difficult to check corruption. Some agency must be evolved so that we can check up.

One officer was shunted out from the steel plant on charges of corruption He got re-employed again in another steel p'ant under Government There was Lamba Committee which tried to find fault with the officers who were responsible for the collapse of the Steel Melting Shop at Rourkela. Is it a fact that those officers who were chargesheeted and who were thrown out of the job had got employment now in the Indian Iron and Steel Company at lucrative pay? We must try to find out where exactly is the snag. With great difficulty we removed even the General Manager of the Rourkela Steel Plant because he was responsible for the collapse of the Steel Melting Shop. We removed him; we even removed the General Superintendent of the Rourkela Steel Plant because he was responsible for the same. We even removed one of the Chief Engineers for the same fault. I want to know how many of them have got appointments in the Indian Iron and Steel Company? If this happens, then where is the morality and where is the sanctity of what we have done.

Mr. Chairman, Sir, even there are officers who have no qualifications; there are officers who have no degrees or diplomas who are now Chief Engineers

There is the case of one other fellow who was at Rourkela. For two years I have been saying that he had submitted all fictitious certificates, degrees and diplomas and there should be some inquiry into it. Vague replies were given. Now, the man has been shunted out of the Rourkela Steel Plant He has got a wonderful job in the Bharat Coking Coal, and he is probably the general manager of a coal washery. The reply that I have got from the hon Minister is that his certificates were verified during the time of the interview If they were verified during the time of interview, and 15 to 20 years have elapsed in the meantime, why should he not ask him to submit the originals? If it happens to be the case of a worker, it takes only five minutes to throw him out of the job, but because he was the chief engineer, Government would take a mighty long time to decide whether they would have some agency to verify the certificates or not. This is the difference between the workers and others

I would submit also that there should be a personnel policy in the steel plants, and those who are personnel officers must have a different attitude in the present context of things. The old personnel management system cannot continue in this

age. The Rourkela steel plant or any other steel plant, for that matter, has lost production due to power failure, this, that and the other. But one main factor for the loss of production is that the management-labour relation has also deteriorated, and Government are fully aware of it. Why is there this deterioration? They have had to give the workers so many incentives, one incentive to earn a little more money, a little bonus to earn a little more money and so on. This is as of bribing the workers. After all, one is paid for the work that one has put in for eight hours or so. Why should there be so many incentives? This means that there is no yardstick to know whether he has actually worked for those eight hours or not. You may try to give him a little good food, and a little more money, and try to put it into his head that if he works well he would get these incentives. This is almost like a capitalist system. We must try to evolve a system by which the worker gives of his best and gets the best also.

As far as the Rourkela steel plant is concerned, the plant could not produce more because the Orissa State Electric Supply Corporation could not give power to it. But in Rourkela there is a thermal power plant with a capacity of 125 MW or there abouts. Why did the management not try to utilise that thermal power plant? If it did work? I think if it would have worked to the extent required, there would not have been fall in production at all. I understand that they did not utilise that thermal power plant.

My last submission is that the Rourkela steel plant in Orissa has become a vulnerable spot in the sense that there is no regional peace in Rourkela Mr. Siddhartha Shanker Ray is worried in West Bengal, and it may be that Mrs. Nandini Satpathy may be worried in Orissa. There has been peace delegation from Bengal to Rourkela and from Rourkela to Bengal. Somewhere, there is trouble; somewhere there is difficulty and somewhere there is some snag. I appeal to the hon. Minister to kindly note that something very serious is coming up. Only last week when I was at Rourkela, I saw a hand-bill which was full of fascist dicta and there was regionalism galore. So, I appeal to the hon. Minister to go into root cause of it and try to solve it so that there may be industrial peace not only in Rourkela but elsewhere too.

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, सब से पहले मैं भिलाई इस्पात कारखाने के मजदूरों, अफसरों और मैनेजमेंट को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस कारखाने ने अपनी क्षमता को 94 परसेंट सेलेबिल स्टील का उत्पादन किया है जोकि किसी कारखाने ने, चाहे वह रूरकेला हो, दुर्गापुर हो या टाटा हो या कोई अन्य हो, ज्यादा है, किसी ने भी उतना नही किया है जितना कि भिलाई वालों ने किया हैं । इस बात का सारा श्रेय मजदूरों को है ।

1972–73 की तुलना में इस मजदूरों को कम वेत्तन पैकेट मिला है । यह गर्व की बात है कि 1972–73 की अपेक्षा 1973–74 में मजदूरो को वेत्तन पैकेट कम मिला है और महंगाई बढ़ी है, फिर भी उन्होंने शान्ति के साथ उत्पादन बढ़ाया । यह एक आदर्श है । मैं इस बात के लिए खास तौर से मंत्री महोदय और मंत्रालय के अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब बोनस का सवाल आये उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें ।

[चन्दूलाल चन्द्राकर]

इसी तरह से मैं मध्य प्रदेश के बिजली विभाग को भी, उन के कर्मचारियो को भी धन्यवाद देता हू कि देश भर मे बिजली की कमी होते हुए भी इस विभाग ने भिलाई के इस्पात कारखाने को एक मिन्ट के लिए भी बिजली की कमी नही होने दी और पूरी बिजली सप्लाई की । भिलाई इस्पात कारखाने मे अगर कोयले की कमी नही होती तो इस वर्ष वहां के मजदूर एक नया रेकार्ड उपस्थित करते । उत्पादन के क्षेत्र मे उन्होने 94 प्रतिशत मे नेविल स्टील का उत्पादन किया जब कि कोयले की कमी थी । अगर कोयला होता तो इस से भी अधिक उत्पादन का आश्चर्यजनक रेकार्ड स्थापित करते ।

इस वर्ष जो दुर्गापुर, रूरकेला और टाटा मे उत्पादन की कमी हुई है उस से हम को सबक लेना चाहिए, सोचना चाहिये, कि क्या बात है। इस साल वहा बिजली और कोयले की कमी हुई। मैं समझता हू कि यह समय आ गया है कि भिलाई को छाड कर दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात के कारखाने मे कैप्टिव पावर प्लाट तत्काल लगाया जाए। दूसरे यह कि किसी भी तरह से जो कोयले की कमी हुई है उस पर विचार किया जाय जिस से इस तरह से भविष्य मे कोयले की कमी न होने दे । यह भी सुनने मे आया है कि भारत कोकिग कोल खान डिपार्टमेंट मे चला जायेगा । मैं समझता हू कि यह गलत कदम होगा अगर ऐसा हुआ तो कोयले की फिर से कमी होगी जिस से इस्पात के उत्पादन को नुकसान हो सकता है ।

जो भी इस वर्ष का अनुभव था जैसे 1973-74 में विभिन्न उद्योगो मे हडताले हुई, औद्योगिक अशान्ति रही, लेकिन इस्पात कारखानो मे ऐसा क्यो नही हुआ ? इस का एक मुख्य कारण यह है कि हमारे स्वर्गीय इस्पात मत्री श्री मोहनकुमार मगलम ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है जोइट निगोशियेशन्स कमेटी की । जब कभी भी समस्या उत्पन्न होती है तो जौइट निगोशियेशन्स कमेटी मे मैनेजमेट के, स्टील विभाग के प्रतिनिधि और मजदूरा के प्रतिनिधि बैठते है और समस्या को आपस मे बैठ कर हल करते है । मैं समझता हू यह एक आदर्श उपस्थित किया गया है जो अन्य उद्योगो मे भी लागू करना चाहिये ।

अब मैं इस्पात कारखाने के सचालन कमजोरिया की ओर मत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हु । सबसे कमजोरी मेनेजमेन्ट की है । सभी इस्पात कारखानो मे इस की कमी है जिसकी वजय से अनेक दुर्घ नाये होती है और जहा भी मेन्टेन्स खराब हुआ तो उस के जिम्मेदारी अधिकारी की तरक्की होती गई जितने कारखाने है आप उन के मेन्टेन्स की ओर ध्यान दें।

दूसरे यह कि कारखानो मे चोरिया बहुत होती है। चोरिया कई तरह की होती है— चाहे स्टील चुरा ले जाये या चाहे स्क्रेप मे अच्छे स्टील को डाल देते है। इन को अगर रोका जाय तो इस्पात कारखाने की काफी आमदनी बढ सकती है और घाटा पूरा हो सकता है।

तीसरी कमजोरी औद्योगिक संबंधी की है। हमारे औद्योगिक संबंध में, यहां तक कि कारखानों में अनेक कर्मचारी बिना किसी कारण के नौकरी से हटा दिये जाते है, जैसे रूरकेला स्टील प्लान्ट में जो फ़ार्टिलाइजर प्लान्ट है वहां चार आदिवासियों को बिना किसी कारण के हटा दिया गया है। इसी तरह से भिलाई में भी हुआ है। इन घटनाओं से औद्योगिक संबंध बहुत बिगड़ते हैं, और यहां तक होता है कि जो अफ़सर होते है वह ईमानदार कर्मचारियों को सजा देते हैं और जो हेराफरी करने वाले उन को प्रोत्सहान देते हैं।

चौथी कमजोरी ठेकेदारी प्रथा की है। मैं समझता हूं कि ठेकेदारी प्रथा चाहे कोयले, लोहे को रेलों में चढाने या उतारने के काम में हो, या अन्य काम हो, ठेकेदारी प्रथा को पूर्णत: बन्द करना चाहिए। इससे बहुत नुकसान हो रहा है।

इसी तरह से हमारे स्टील प्लांट में जो उत्पादन नहीं बढ़ रहा है उस का एक मुख्य कारण यह है कि जो मैल्टर्स होते है वह विदेशों में ट्रेनिंग लेकर आते हैं और उन का वेतन 700, 800 रुपये महावार तक ही बढ़ पाता है, उसके आगे उन का वेतन नही बढ़ता। इसलिए विशेषज्ञ होते हुये भी वह डिपार्टमेंट के ऐडमिनिस्ट्रेटिव पदों मे चले जाते हैं क्योंकि उन को वहां अधिक वेतन मिलता है। नतीजा यह होता कि जो अच्छे टेक्नीशियन्स होते हैं उनका उत्पादन बढ़ाने में उपयोग नहीं होता, वह लोग दूसरी जगहों पर चले जाते हैं जिस से कारखानों को लाभ नहीं होता है दूसरे देश मैल्टर्स तनख्वा; मैनेजर्स से ज्यादा होते हैं, जब कि हमारे देश में 700, 800 रु० से ज्यादा नहीं होती।

जैसा पूर्व वक्ता ने कहा स्क्रेप की बिक्री करने की ऐसी प्रणाली होनी चाहिये जिस से कर्मचारी अनापशनाप पैसा न कमा लें, सकें, गोलमाल न कर सकें। इसलिये इस बारे में स्पेशल व्यवस्था की जानी चाहिये।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member will continue tomorrow if he wants to. Now, Shri K. Raghu Ramaiah.

17.59 hrs.

RE. STATEMENT ON BIHAR SITUATION

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Regarding some points *vis-a-vis* the Bihar situation made this morning, there was a meeting of the Business Advisory Committee and it was decided there that the Home Minister would be making a statement the day after tomorrow, and thereafter the Business Advisory Committee would meet again to decide whether and if so what discussion would be necessary and when.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): What about the statement of the Health Minister tomorrow?

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Tomorrow.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 16, 1974/Chaitra 26, 1896 (Saka).....

MGIPND—330 LS—1-6-74—978